रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-552/2020/989/22-2-2020-17(408)/2017

लखनऊ:दिनांक: 17 दिसम्बर, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्तान (बन्दी संख्या-41716) पुत्र श्री गफ्फार, निवासी झलरा, थाना-कोतवाली, जनपद-बिजनौर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-808/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-1, बिजनौर के आदेश दिनांक 18.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा यथावत रखा गया, दयायाचिका समिति द्वारा उक्त बन्दी की आयु, कारावास में भोगी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण, जेल मैनुअल के प्रस्तर-196 के अन्तर्गत मेडिकल बोर्ड द्वारा बतायी गयी बन्दी की अशक्तता एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-552/2020/989(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
3- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in